सरकार ने दी 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक को मंजूरी

[पीटीआई | नई दिल्ली]

सरकार ने बुधवार को 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दे दी। चीनी के बंपर उत्पादन की वजह से यह फैसला लिया गया है। इससे चीनी मिलों को किसानों का 15 हजार करोड़ से अधिक का बकाया चुकाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ने के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 2019-20 मार्केटिंग ईयर के लिए 275 रुपये क्विंटल पर बरकरार रखा गया है।

शुगर का मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। गन्ने के मामले में एफआरपी वह न्यूनतम कीमत होती है, जिसका किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है यानी इससे कम कीमत पर उनसे गन्ना नहीं खरीदा जा सकता। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने खाद्य मंत्रालय के 40 लाख टन शुगर के बफर स्टॉक के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। पिछले साल अगस्त में केंद्र ने 30 लाख टन शुगर के बफर स्टॉक का ऐलान किया था, जिस पर 1,175 करोड़ रुपये की लागत आई थी। केंद्र ने पिछले साल भी मिलों की कैश की स्थिति में सुधार के लिए यह कदम उठाया था। सरकार के बफर स्टॉक बनाने से मिलों को चीनी का स्टॉक निकालने में मदद मिली और उन्हें उससे कैश मिला। इस पैसे का इस्तेमाल मिलों ने किसानों का बकाया चुकाने के लिए किया था। मौजूदा 2018-19 मार्केटिंग सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 3.29 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, जबकि देश में सालाना 2.6 करोड़ टन चीनी की खपत होती है। शुगर इंडस्ट्री की संस्था इस्मा का कहना है कि 1 अक्टूबर 2019 तक शुगर का स्टॉक 1.45 करोड़ टन के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, आमतौर पर इसे 50 लाख टन होना चाहिए। इस्मा ने पहले बताया था कि 2019-20 में गन्ने का रकबा 49.31 लाख हेक्टेयर रह सकता है, जो 2018-19 के गन्ना सीजन के 55.02 लाख हेक्टेयर से कम है।

उसने उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन करीब 1.2 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया था, जो चालू वर्ष में 1.18 करोड़ टन के अनुमान के लगभग बराबर है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना क्षेत्र 2019-20 के लिए करीब 30 प्रतिशत घटा है। इसका कारण सितंबर 2018 के बाद बारिश कम होना है। इससे गन्ने की खेती पर असर पड़ा। इसके कारण राज्य में चीनी का उत्पादन 2018-19 में घटकर करीब 70 लाख टन रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में गन्ने का रकबा कम हुआ है। इससे राज्य में चीनी उत्पादन 2018-19 के 43.6 लाख टन से घटकर 35 लाख टन रहने का अनुमान है।

275 रुपये रहेगा FRP

- **सरकार** ने गन्ने के FRP में कोई बदलाव नहीं किया है, इसे 2019-20 मार्केटिंग ईयर के लिए 275 रुपये क्विंटल पर बरकरार रखा गया है
- **मौजूदा 2018-19** मार्केटिंग सीजन में चीनी का उत्पादन 3.29 करोड़ टन रहने की उम्मीद, देश में सालाना 2.6 करोड़ टन खपत होती है

Economic Times
25/7/19